



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012020-215659
CG-DL-E-23012020-215659

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22|
No. 22|

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2020/माघ 02, 1941
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2020/MAGHA 02, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2020

सं.16(35)/2018-एनईआरएस.—केंद्र सरकार, दिनांक 7 जनवरी, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की 'लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह औद्योगिक विकास स्कीम (एलएनआईडीएस), 2018' नामक अधिसूचना संख्या 16(35)/2018-एनईआर दिनांक 1 जनवरी, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

1. पैरा 3 में 'शुरुआत और अवधि' शीर्षक के तहत 'यह 01.04.2018 से लागू होगी तथा 31.03.2020 तक पंजीकृत इकाइयों के लिए 31 मार्च 2025 तक प्राप्त प्रतिबद्ध दायित्वों सहित 31.03.2020 तक प्रभावी रहेगी' शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:- 'यह 01.04.2018 से लागू होगी तथा 31.03.2021 तक पंजीकृत इकाइयों के लिए 31 मार्च 2025 तक प्राप्त प्रतिबद्ध दायित्वों सहित 31.03.2021 तक प्रभावी रहेगी'।

राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2020

F.No.16(35)/2018-NERS.—The Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India, Ministry of Commerce & Industry's Notification No.16(35)/2018-NER dated 1st January, 2019 titled "Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands Industrial Development Scheme (LANIDS), 2018 as published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section 1, dated 7th January, 2019 :—

1. In paragraph 3 under the heading "**Commencement and duration**" for the words: "It will be effective from 01.04.2018 and will remain in force up to 31.03.2020 with committed liabilities accrued up to 31st March, 2025 for units registered up to 31.03.2020" following may be substituted: "**It will be effective from 01.04.2018 and will remain in force up to 31.03.2021 with committed liabilities accrued up to 31st March, 2025 for units registered up to 31.03.2021**".

RAJENDRA RATNOO, Jt. Secy.